

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
बहुम् (पौनसून)– सत्र
दर्ग– ही

16 भाद्र, 1943 [रु०]
को
निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक—
07 सितम्बर, 2021 [इ०]

झारखण्ड विधान- सभा के आदेश- पत्र पर अकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई साठ संख्या	सदस्यों का नाम	संविष्ट विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
का 01-अ०स०-०९	श्री सरयू राय	जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	26.08.2021	

नोट— का 01-अ०स०-०९ दिनांक— 06.09.2021 से सदन द्वारा दिनांक— 07.09.2021 को लिए स्थगित।

रीची,
दिनांक— 07.09.2021

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रीची।

झापाक— झा०पि०स० (प्रश्न)— 01/2021— 2046...../विभा०, रीची, दिनांक— 06/09/21
प्रति— झारखण्ड विधान सभा के गा० सदस्यगण/गा० मुख्यमंत्री/गा० नेता प्रतिपक्ष/गा०
मन्त्रिमण/मुख्य सचिव तथा गा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/सोकार्यकाल के आप सचिव एवं सरकार के सभी
विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्रीरामेश्वर
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रीची।

-::2::-

ज्ञापांक— ज्ञानविद्या० (प्रश्न)– ०१/२०२१— २०५६ /विद्या०, रोंची, दिनांक—०६/०९/२१

प्रति— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव/निजी सहायक, सरितीय कार्यालय को लगभग माननीय उच्चस्तु महोदय/सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के उप सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

२०५६
०६/०९/२१

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रोंची

ज्ञापांक— ज्ञानविद्या० (प्रश्न)– ०१/२०२१— २०५६ /विद्या०, रोंची, दिनांक—०६/०९/२१

प्रति— कार्यपाली शास्त्रा/आश्वासन समिति शास्त्रा एवं वेबसाइट शास्त्रा को सूचनार्थ प्रेषित।

२०५६
०६/०९/२१

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, रोंची



सत्यमेव जयते

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम् (मॉनसून) सत्र
अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-०१

मंगलवार, दिनांक 16 भाद्र, 1943 (श०) ----- को
07 सिम्बार, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या- ०१ (एक)

(१) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग- ०१ (एक)

कुलयोग- एक (०१)

श्री सरदू राय	प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ज्ञारखण्ड राज्य रथापना दिवस समारोह, 2016 में गायिका सुनिधि चौहान को कुलने का निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक- 09.11.2016 को हुई बैठक में दिया गया, जिसपर उनके वरीय आप्त सचिव ने विभाग को प्रस्ताव दिया कि इस कार्यक्रम पर ₹ 44,37,250/- खर्च होगा।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुरिप्ति- यह है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक- 09.11.2016 को हुई बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में उनके वरीय आप्त सचिव के बाघ्यम से Archers Entertainment Private Limited. द्वारा ₹ 44,27,500/- (बीचालीस लाख सताईस हजार, पौंछ रुपये) मात्र पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु भाव पत्र प्राप्त हुआ (Archers Entertainment Private Limited.) से प्राप्त भाव पत्र की (छायापति संलग्न)।
2. क्या यह बात सही है कि सुनिधि चौहान का गायन सूर्यमंदिर समिति, सिद्गोडा, जमशेदपुर में दिनांक- 06.11.2016 की शाम हुआ था, जिसके संरक्षक तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री थे।	सचिवित नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य रथापना समारोह, 2018 में सुनिधि चौहान के कार्यक्रम पर कुल ₹ 55,22,281/- खर्च हुआ, जो स्वीकृत खर्च ₹ 44,47,500/- से ₹ 10,94,781/- अधिक है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुरिप्ति यह है कि- (i)- Archers Entertainment Private Limited. से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार ₹ 44,27,500/- पर सुनिधि चौहान के गायन कार्यक्रम हेतु Archers Entertainment Private Limited. का चयन मानोन्यन के आधार पर करते हुए विभागीय पत्रांक- 1423, दिनांक- 11.11.2016 द्वारा उपायुक्त, रोची को ₹ 44,27,500/- मात्र पर कार्यक्रम का आयोजन करने, तत्संबंधी राशि का भुगतान करने एवं Archers Entertainment Private Limited. के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन, भोजनादि एवं बाहन की व्यवस्था होटल रेडिसन ब्लू, रोची में करने का निर्देश दिया गया (छायापति संलग्न) (ii)उक्त के आलोक में उपायुक्त, रोची द्वारा Archers Entertainment Private Limited. से प्राप्त भाव पत्र के अनुसार कार्यक्रम हेतु ₹ 44,27,500/- मात्र का भुगतान किया गया है।

<p>निम्नलिखित की दो प्रतिवेदनों के अनुसार कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है। इनमें से एक विवरण यह है कि उपर्युक्त कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है। इनमें से एक विवरण यह है कि उपर्युक्त कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है।</p>	<p>(iii)- Archers Entertainment Private Limited. के मुख्य कलाकार एवं सहायक कलाकार के आवासन एवं मोजनादि पर ₹ 2,97,084/-वाहन की व्यवस्था पर ₹ 58,525/- वाहन के लिए टिकट पर ₹ 7,42,172/- अर्थात् कुल ₹ 10,97,791/- (दस लाख, संतानवे हजार, सात सौ एकानवे) मात्र का व्यय हुआ है। अर्थात् सुनिधि बौहान के गावन कार्यक्रम हेतु कुल ₹ 55,25,291/- (पचास लाख, पच्चीस हजार, दो सौ एकानवे) मात्र का नुगलान उपायुक्त, रोची हारा किया गया है (उपायुक्त, रोची का पत्राक-921 (ii) / नजारा, दिनांक- 13.12.2016 की (धायाप्रति संलग्न)</p>
<p>निम्नलिखित की दो प्रतिवेदनों के अनुसार कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है। इनमें से एक विवरण यह है कि उपर्युक्त कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है।</p>	<p>(iv). कायौपरांत उपायुक्त एवं सकाग शंखा/एजेंसी का व्यवन मनोनयन के आधार पर करने के प्रस्ताव, कराये गये विभिन्न कार्यों एवं उनपर व्यय हुई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति गत्रिपरिषद् के दिनांक- 28.12.2016 को हुई बैठक में प्रदान की गयी है।</p>
<p>4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुनिधि बौहान के दिनांक- 06.11.2016 के जमशेदपुर कार्यक्रम पर हुए व्यय की तुलना में स्थापना दिवस समारोह, 2016 के कार्यक्रम पर अत्यधिक व्यय करने के जिम्मेदार व्यक्ति पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई ली गयी है, नहीं तो क्यों?</p>	<p>वस्तुरिथमि उपर्युक्त कलिका में वर्णित है।</p>

सुनाधि/- निम्नलिखित की दो प्रतिवेदनों के अनुसार कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है। इनमें से एक विवरण यह है कि उपर्युक्त कलाकारों के लाभ के बारे में विवरण दिया जाता है।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

षष्ठम (मानसून) सत्र

वर्ग-02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक—

16 भाद्र, 1943 (श०)

को

07 सितम्बर 2021(ई०)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को संबूधित की गई संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
✓ 22	अ०स०-30	श्री बंधु तिकी,	डफिंग यार्ड हटाना	खान एवं भूतत्व	02.09.21
✓ 23	अ०स०-09	सुश्री अम्बा प्रसाद,	रिक्त पदों पर नियुक्ति	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	26.08.21
✓ 24	अ०स०-10	श्री प्रदीप यादव,	योजना को प्रभावी बनाना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	30.08.21
✓ 25	अ०स०-15	श्री दीपक विलवा,	कर्मियों को वेतनादि का भुगतान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	30.08.21
✓ 26	अ०स०-27	श्री समरी लाल,	निर्माण कार्य पूर्ण करना	स्वाठीशिरोंगी एवं परिवर्तन	02.09.21
✓ 27	अ०स०-25	श्री राजेश कच्छप,	प्रजनन केन्द्र का जीणोंद्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	परिवर्तन	02.09.21
✓ 28	अ०स०-01	श्रीमती सीता सोरेन,	निर्माण कार्य पूर्ण करना	स्वाठीशिरोंगी एवं परिवर्तन	26.08.21
✓ 29	अ०स०-14	श्री लम्बोदर महतो,	समुचित कार्रवाई कराना	परिवर्तन	
✓ 30	अ०स०-13	श्री अमर कुमारी बाउरी,	ऑक्सीजन स्टांट लगाना	खान एवं भूतत्व	30.08.21
✓ 31	अ०स०-24	श्री राजेश कच्छप,	थिकिल्सकों को अन्य सभी लाभ देना	स्वाठीशिरोंगी एवं परिवर्तन	02.09.21
✓ 32	अ०स०-21	श्री विरंधी नारायण,	ऑनलाईन बिक्रय की सुविधा देना	परिवर्तन	31.08.21

1.	2.	3.	4.	5.	6.
33— अ०स०—06	डॉ० सरफराज अहमद,	बकाया मानदेय का भुगतान भवन का हरसांतरण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	26.08.21
34— अ०स०—26	श्री संजीव सरदार,	वेड की सख्ता बढ़ाना	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	02.09.21
35— अ०स०—17	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	नक्से को सत्यापित कराना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	30.08.21
36— अ०स०—12	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	स्वास्थ्य फैन्डों को दुरुस्त कराना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	30.08.21
37— अ०स०—04	श्री विनोद कुमार सिंह,	प्रतिनियुक्ति की समीक्षा	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	26.08.21
38— अ०स०—20	प्रो० स्टीफन मराण्डी,	म्युजियम एवं पुस्तकालय का निर्माण	पर्यटन, कला संस्कृति खेल—कूद एवं युवाओं	पर्यटन, कला संस्कृति खेल—कूद एवं युवाओं	02.09.21
39— अ०स०—29	श्रीमती ममता देवी,	नियमित पढ़ाई शुरू कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26.08.21
40— अ०स०—02	श्रीमती सीता सोरेन,	दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	31.08.21
41— अ०स०—11	श्री प्रदीप यादव,	प्रशिक्षकों की सेवा नियमित कराना	पर्यटन कला संस्कृति खेल—कूद एवं युवा का,	पर्यटन कला संस्कृति खेल—कूद एवं युवा का,	26.08.21
42— अ०स०—03	श्री राज सिन्हा,	आखण के तहत प्रोम्भति	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	31.08.21
43— अ०स०—19	श्री नलिन सोरेन,	प्रदूषण को रोकना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	26.08.21
44— अ०स०—07	श्री सुदिव्य कुमार,	निदेशक की नियुक्ति	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	31.08.21
45— अ०स०—22	श्री दुलू महतो,	इनकैथ श्रमिकों का बकाया भुगतान	उद्योग	उद्योग	30.08.21
46— अ०स०—16	श्री सरयू राय,	घेड पे लागु कराना	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	स्वाधिरणि० एवं परिर० कल्याण	02.09.21
47— अ०स०—28	श्री दशरथ गागराई,	नियुक्ति पत्र देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	31.08.21
48— अ०स०—23	डॉ० लम्बोदर महतो,	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, औद्योगिक इकाईयों की जांच	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	26.08.21
49— अ०स०—08	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, औद्योगिक इकाईयों की जांच	विद्यालय को पूर्ण रूप से खोलना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	31.08.21
50— अ०स०—18	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता				

रांधी
दिनांक—07 सितम्बर, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांधी।
क०प००३० /

(03)

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020- 2043 /विभाग, रांची, दिनांक- ५/९/२१

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्यमंत्री ०५/०९/२१

(अनूप कुमार लाल)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020- 2043 /विभाग, रांची, दिनांक- ५/९/२१

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव/आप सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्यमंत्री ०५/०९/२१

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-03/2020- 2043

/विभाग, रांची, दिनांक- ५/९/२१

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/वेबसाइट शाखा/जे.भी.एस. टी.भी. शाखा/ऑनलाइन शाखा/प्रश्न व्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्यमंत्री ०५/०९/२१

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची।

०५/०९/२१

(22)

श्री बंधु तिर्की, सठविंसठ द्वारा दिनांक—07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न
संख्या—अ०स०—३०

वया मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा नगर परिषद् क्षेत्र के घनी आबादी के मध्य हिंडालको कम्पनी का "डम्पिंग यार्ड" अवस्थित है।	स्थीकारात्मक। कृपया कडिका—४ दृष्टव्य।
2	क्या यह बात सही है कि हिंडालको कम्पनी द्वारा पर्यावरण एवं नगर परिषद् क्षेत्र अधिनियम का उलंघन कर "डम्पिंग यार्ड" संचालित किया जा रहा है, जिससे घनी आबादी प्रदूषित हो रही है;	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद से संबंधित है। पर्वद द्वारा निर्गत CTO की छायाप्रति संलग्न है।
3	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा नगर परिषद् क्षेत्र में हिंडालको कम्पनी द्वारा संचालित बौंकलाइट पत्थर से भरा "रोपदे" घनी आबादी के ऊपर से गुजरने के कारण हमेशा जान—माल का खतरा बना रहता है;	यथा उपरोक्त।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्थीकारात्मक हैं, तो वया सरकार लोहरदगा नगर परिषद् की घनी आबादी क्षेत्र से "डम्पिंग यार्ड" एवं "रोपदे" को अन्यत्र हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हीं तो कबलक नहीं तो क्यों ?	जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक दिनांक—22.01.2021 में हिंडालको कम्पनी के प्रतिनिधि को वर्तमान डम्पिंग यार्ड को बड़कीचापी में Shift करने के निवेश के आलोक में हिंडालको कम्पनी ने अपने पत्रांक—Ref. HIL/LHD/ SIDING / ADMINLHD/224 दिनांक—03.09.2021 द्वारा सूचित किया है कि डम्पिंग यार्ड को बड़कीचापी में Shift करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

झापांक—विंस०(अ०स०)—९८/२०२१ १७२५ / एम०, रौची, दिनांक—०६.११.२१
प्रतिलिपि—अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रौची को उनके झाप सं० प्र०—२००७ दिनांक—०२.०९.२०२१ के संदर्भ में 200 प्रतियो के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सं० १७२५
सरकार के उप सचिव



(10)

REF: HIL/LHD/SC01NG/ADMNL/HO/2241.

Date - 03rd September 2021

To,
The Officer on Special Duty,
Lohardaga, Jharkhand

Sub: Reply of quarry No. 30 of Vidhan Sabha

Ref: Your letter No. 292 dated 03.09.2021 and letter No. 4007 dated 02.09.2021 from Vidhan Sabha
Secretariate, Jharkhand

Sir,

With reference to the above subject and Ref. we are hereby submitting our responses regarding
quarry raised in the said letters:

1. Yes, Lohardaga siding is located in the populated area of Lohardaga. The siding was in operational since 1948 and covering an area of 21.362 acres. We are paying around Rs. 1 crore rent to the railway per month. Almost we have generated 360 employment for tribal people in and around Lohardaga.
2. No sir, we are taking all precautionary measures to protect the environment. As a group's philosophy, our prime focus is to save and protect the environment. We would like to mention here that, Lohardaga Railway Siding is in operation since 1948 and connected to our Bagru Group of mines through Aerial ropeway (9.88 Km aerial distance). We used to despatch our entire bauxite from Bagru group of mines to Lohardaga siding via Aerial Ropeway, which is the best eco-friendly transportation system. No truck transportation through road is being done from Bagru group of mines. Thus, we are not creating any environmental pollution in Lohardaga town. Instead we are protecting the environment of the surrounding by eco-friendly transportation through aerial ropeway. All unloading infrastructures are readily available at Lohardaga siding and the siding is fully mechanised in nature and also having fully automated system. Moreover, we have also installed Telescopic Chute at Lohardaga siding to arrest the fugitive dust and mitigate sound pollution to protect the environmental pollution. From Telescopic Chute the Bauxite is being discharged to Railway loading point through covered belt conveyor, thus mitigating the generation of fugitive dust and noise which shows our seriousness and dedication towards environment. Apart from Aerial ropeway, Bauxite from other sources is also being despatched to Lohardaga siding through truck transportation covered with tarpaulin to arrest the dust in a safe manner.

Hindalco is also complying all statutory conditions mentioned in CTO, Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) and MoEF&CC used to visit our Lohardaga siding regularly to check the compliance status of all conditions. As per CTO condition, we have already planted around 10000 saplings of various species including fruit bearing in the siding premises which has now become dense forest. We have also constructed 10 feet high boundary wall in the

Hindalco Industries Limited
Alumina Division, Court Road, Lohardaga 835302, Jharkhand, India
T: +91 6526 224112/224015/223113 | E: hindalco@hindalco.com | W: www.hindalco.com
Registered Office: Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 053, India
T: +91 22 66917000 | E: +91 22 66917001
Corporate ID No.: L27D2017HINDALCO

Scanned By Scanner Go

(9)

siding and constructed concrete road all along the siding premises as per CTO condition. Water jets have also been installed at the transfer points of ropeway to arrest the release of dust. Water sprinkling is done on daily basis to mitigate the air pollution. JSPCB has also appreciated all our efforts pertaining to the compliances towards protecting the environment.

Regularly, we are monitoring Ambient Air Quality by NABL accredited Lab approved by JSPCB and all the parameters are within the permissible limit (Please see the last 3 years parameters of Ambient Air Monitoring) which clearly shows that the pollution level has not increased throughout the years.

Parameters	FY-19 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	FY-20 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	FY-21 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Permissible Limit
PM-10	57.3-79	25.9-75.0	24.1-83.2	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM-2.5	31-41	31.1-44.0	17.8-48	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SOX	2.9-4.2	2.7-4.7	2.3-5.7	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NOX	5.1-5.9	2.3-6.6	4.9-24.0	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

As per the new guideline by JSPCB, online analyser of PM-10 has also been installed at Siding which is connected with JSPCB server with real time data. This is also a step towards the environmental protection measures taken at Railway siding.

We have taken all required permissions from different Govt. agencies.

Based on the above facts and figures, it is clearly stated that the pollution level has not been increased at our Lohardaga siding by implementing several protection measures towards environment.

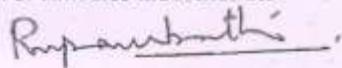
3. No sir, since last 15 years no accident had happened due to ropeway transportation. We believe in responsible and sustainable business practices and always keen to adopt best safety practices. We have installed rope safety cage, limiting switch in our ropeway system. We have already implemented digitalisation in our ropeway system.
4. However, we are planning to shift the Lohardaga siding to Barkichanpi area. We have already identified the required land for constructing of new Railway siding which is located in village Barkichanpi, dist- Lohardaga. We have planned to construct the new railway siding at Barkichanpi area for loading and unloading of bauxite. The entire bauxite being despatched to Lohardaga siding by truck transportation will be unloaded at the proposed Barkichanpi railway siding whereas, Bauxite being despatched from Bagru Group of mines will continue to transport to Lohardaga siding through aerial ropeway as per the directives given by Central Pollution Control Board (CPCB), New Delhi vide letter No -B-33014/7/2010/PCI-II/complaint/10799 dated 09.02.2015.

(8)

Hindalco has given nos. of deliberations to District administration, Lohardaga regarding this new project. Nos. of meetings held with Railway officials for the new project and they have also shown their interest. Bidhan Sabha team also inspected our Lohardaga siding and were told that the new siding will be constructed at Barki Champi area. They also convinced with our proposal. The bauxite transporting through trucks from other mines except Bagru group of mines will be shifted and unloaded in a separate railway siding. However, we are in an advanced stage for shifting Lohardaga siding to Barki Champi area. It may complete by March, 2022.

Thanking You,

For Hindalco Industries Ltd.



General Manager – Operations

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय संविधानसभा द्वारा दिनांक—07.09.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या—अ०स०—०९ का उत्तर :—

प्रश्न	उत्तर
1— क्या यह बात सही है कि साध्य का करीब 30% लोक वन लोक है तथा इसे संरक्षित करने और बढ़ागे में एसीएफ, रेज ऑफिसर, बनपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।	स्वीकारात्मक। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% (लगभग 30%) भू-भाग वन भूमि है। इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन में अन्य वन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ ये इगमित वन पदाधिकारी भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं।
2— क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से एक बार भी नियुक्ति नहीं हुई।	स्वीकारात्मक। सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। परन्तु प्रोन्नति से समय-समय पर नियुक्तियाँ हुई हैं।
3— क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर भारी शिकित्याँ हैं, रेज ऑफिसर 3-4 रेज तक के अतिरिक्त प्रभार में हैं, जिनमें लगभग लगानी वनपाल है तथा 2-3 वर्ष में लगभग सभी रेज ऑफिसर रिटायर हो जाएंगे और ऐसे में हमारे वनों का संरक्षण और विकास विकट रूप से प्रभावित होगा।	स्वीकारात्मक। इन तीनों संघर्षों में सम्भाली काफी शिकित्याँ हैं। भविध में कुछ और सेवानिवृत्तियाँ भी होगी।
4— यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पड़े खण्ड-1 में वर्णित पदों पर इसी क्षेत्र नियुक्ति कर बेरोजगारों को बेरोजगार देने तथा वन संपदा का संरक्षण एवं विकास सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	इन पदों पर नियुक्ति का विषय प्रक्रियावैन है।

झारखण्ड सरकार
बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक—०५ / किसानसभा अल्पसूचित प्रश्न—११९/२०२१—२५७०८०४०, रोची, दिनांक—०६.०९.२०२१

प्रतिलिपि—उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रोची को उनके ज्ञाप संख्या—१७८९ दिनांक—२८.०८.२०२१ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, भौतिकाल संविवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रोची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रोची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

(24)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सभ्योसंघ द्वारा दिनांक-07.09.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित
प्रश्न संख्या-अ०स०-१० का उत्तर :-

प्रश्न	उत्तर																		
१- क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री वन-जन योजना समिलित है,	स्वीकारात्मक।																		
२- क्या यह बात सही है कि अबतक सही प्रचार-प्रसार के अभाव में राज्य के सभी प्रखण्डों के स्तर तक इस योजना का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाया है, और न ही विभाग द्वारा यह विवरण जारी किया गया है, कि अब तक कुल किटने प्रखण्डों में किटने किसानों को उपरोक्त योजना का लाभ मिल पाया है,	अस्वीकारात्मक। योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रचार-प्रसार हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी को नौँडल पदाधिकारी बनाया गया है। इस योजना का प्रारंभ 2016-17 में हुआ था। लद से इसका प्रचार-प्रसार 24 नौँडल वन प्रमंडल पदाधिकारियों के द्वारा वन समितियों तथा कृषकों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। राज्य स्तर पर समाचार पत्र, F.M. तथा फिल्मों के जरिए भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 24 जिलों में लाभुकों द्वारा इसका कार्यदा उठाया गया है, जो निम्नवत है—																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>लाभुकों की संख्या</th> <th>पैसों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016-17</td> <td>555</td> <td>332029</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>275</td> <td>140270</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>489</td> <td>428730</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>658</td> <td>761590</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>526</td> <td>506545</td> </tr> </tbody> </table>	वित्तीय वर्ष	लाभुकों की संख्या	पैसों की संख्या	2016-17	555	332029	2017-18	275	140270	2018-19	489	428730	2019-20	658	761590	2020-21	526	506545
वित्तीय वर्ष	लाभुकों की संख्या	पैसों की संख्या																	
2016-17	555	332029																	
2017-18	275	140270																	
2018-19	489	428730																	
2019-20	658	761590																	
2020-21	526	506545																	
३- क्या यह बात सही है कि लाल चंदन का वृक्षारोपण एवं उसके बिक्री हेतु नियम बनाया गया है,	लाल चंदन के वृक्षारोपण एवं बिक्री हेतु अलग से नियम नहीं बनाये गये हैं। झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधान अंतर्गत लाल चंदन भी समिलित है।																		
४- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।																		

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवाय परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक-०५ / विभानसना अल्पसूचित प्रश्न-124 / 2021- २५७४ व०प०, रायी, दिनांक ०६.०९.२०२१

प्रतिलिपि-उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रायी को उनके ज्ञाप संख्या-१९१० दिनांक-३०.०८.२०२१ के प्रसंग में अतिरिक्त २०० प्रतियों के साथ/उप सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रायी/माननीय मुख्यमंत्री को आप सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रायी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सिंहोद्धर
८-९-२१
(संतोष कुमार चौधरी)
सरकार के उत्तर सचिव

(25)

1643
०५/०९/२०२१

श्री दीपक बिरुदा, मानवाधिकार से प्राप्त अल्प सुधित प्रश्न संख्या - ३०८०-१५
वया माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साकारता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	वया यह बत रही है कि 1984-85 के प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यसत् शिक्षक, शिक्षिकार्जों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए पत्रांक- 142 दिनांक 04.02.1989 द्वारा आदेश निर्गत किया गया था।	उत्तर आशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पत्रांक 142 दिनांक 04.02.1989 द्वारा वर्ष 1984-85 चरण के परियोजना विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान के प्रक्रिया एवं नीति निर्धारण किया गया है।
2.	वया यह बत सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S). संo- ९२१/२०११, दिनांक ०५.०९.२०१८ के न्याय निर्णय के तहत उपर्युक्त विद्यालयों में कार्यसत् कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था।	उत्तर आशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न में उल्लिखित वाद के साध-साध इस तरह के कुल 226 वादों में दिनांक ०५.०९.२०१८ को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंत निम्नवत् है - "Under the aforesaid facts and circumstances, considering the each and every aspects of the matter, I hereby direct the respondent-State particularly, Principal Secretary, School Education and Literacy Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi to consider the cases of the petitioners taking into account the aforesaid observations and directions Further, instead of quashing the entire resolution, I hereby direct the Principal Secretary of the School Education and Literacy Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi to come-out with a corrigendum, taking into consideration para-18 of the judgment passed in this case and take all necessary steps for consideration of left over cases of the teaching and non-teaching staff of the Project Girls' High School for their regularization and absorptions and also for payment of their salary with all consequential benefits. Taking stock of the suffering of the teachers and other non-teaching staff who have worked for almost 30 years without any salary, the respondents are directed to complete the entire exercise within a period of two months from the date of receipt/ production of a copy of this order."
3.	वया यह बत रही है कि उपर्युक्त नियोजन एवं न्याय निर्णय निर्गत होने के बाबजूद नियुक्ति से अवश्यक वेतन भुगतान हेतु कोई कारबाई नहीं ली गई, जिससे कई शिक्षक/ कर्मी सेवानिवृत्त हो गये तथा कई सेवानिवृत्त होने के कागार पर है।	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलीक में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में १४३ एलपीए दायर किया है, जिस कारण से न्यायादेश का अनुधालन नहीं किया जा सका है। न्यायादेश निर्गत होने के पूर्व राज्य सरकार ने मानवाधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर संकल्प संख्या १२७२ दिनांक २५.०४.२०१८ निर्गत किया है तथा इस संकल्प की नीति के तहत जो कर्मी आवधारित हो रहे हैं, उनकी सेवा की मान्यता दी जा रही है। संकल्प निर्गत होने की तिथि दिनांक २५.०४.२०१८ के उपरान्त

	<p>कुल 48 शिक्षक एवं शिक्षकोन्तर कर्मियों को मान्यता दी गयी है।</p>
4.	<p>यदि उपर्युक्त स्थानों के उत्तर स्वीकारशास्त्रक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त न्याय निर्णय के ज्ञालोक में प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यक्त शिक्षक कर्मियों वेतनादि का भुगतान करने का विचार रखती है, हीं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</p>

सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक—10 / वि.स.01—120 / 2021 1643

रोकी, दिनांक 05/09/2021

प्रतिलिपि— उप सचिव, झारखण्ड विद्यानसना सचिवालय, रोकी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं जावश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(26)

श्री समरी लाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 07.09.2021 को पूछा जाने वाला अल्प
सूचित प्रश्न सं०—अ०स०—२७ का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि रिस्स के पास विंगत 10 वर्षों से Eye Hospital का कार्य चल रहा है, जो राज्य के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण नेत्र चिकित्सालय साबित होगा;	रिस्स, राँची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का निर्माण कार्य दिनांक 23.06.2014 को प्रारंभ हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि नेत्र चिकित्सालय के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण राज्य की जनता इसके लाभ से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। रिस्स, राँची में पूर्व से नेत्र विभाग क्रियाशील है, जहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मरीजों का समुचित ईलाज किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि इस नेत्र चिकित्सालय के निर्माण में अब तक करोड़ों रुपये व्यय किये जा चुके हैं और शेष निर्माण हेतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है;	रिस्स, राँची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस नेत्र चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए चिकित्सा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक- ३७० (11)

दिनांक- 6.9.2021

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, के ज्ञाप सं०प्र० 1998 / वि०स० दिनांक 02.09.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में प्रेषित।

लाल
6.9.21
सरकार के अधिकारी सचिव

श्री राजेश कच्छप, माननीय सर्वियोसो द्वारा दिनांक—07.09.2021 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0—अ0स०—25 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोधी जिला के ओरमाझी प्रखण्ड के मेरठी नदी पहाड़ों के तलहटी में मुटा प्रजनन केन्द्र पशास्त वर्ष पूर्व से अस्तित्व में है, जिसमें लगभग 30 स्थानीय ग्रामीण दैनिक मजदूर के रूप में नियोजित थे।	अस्वीकारात्मक। यह केन्द्र एक विशिष्ट उद्देश्य अर्थात् मगर प्रजनन हेतु स्थापित किया गया था, जो दिनांक—06.04.2018 तक अस्तित्व में था। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, जिसे केन्द्रीय चिकित्याघर प्राधिकरण ने बंद करने का आदेश वर्ष 2017 में दिया था।
2. क्या यह बात सही है कि मुटा प्रजनन केन्द्र मगरमच्छों के प्रजनन हेतु स्वतंत्र प्रकृति प्रदत्त, खनिज लवण से भरपूर योग्य स्थल है।	अस्वीकारात्मक। उक्त मगर प्रजनन केन्द्र captive प्रजनन के लिये प्रारंभ किया गया था। इसे स्वतंत्र प्रकृति प्रदत्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।
3. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में पदस्थापित रेंजर के अनुरक्षिता के कारण करोड़ों लघुथे खर्च के बाद भी मुटा प्रजनन केन्द्र आज अपनी बदहाली की घरम रीमा पर है।	अस्वीकारात्मक। बूँकि मुटा प्रजनन केन्द्र एक प्रोजेक्ट का नाम है। अतः यद्यपि केन्द्र दिनांक—06.04.2018 से बद हो गया, तथापि इस प्रोजेक्ट में बन होने पदाधिकारी की पदस्थापना होती है। श्री संजय कुमार रजक दिनांक—20.06.2018 से इस प्रोजेक्ट के प्रभार में है, जबकि प्रजनन केन्द्र दिनांक—06.04.2018 से ही केन्द्रीय चिकित्याघर प्राधिकरण (CZA) के निदेश के आलोक में कार्यरत नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्थीकारात्मक हैं तो क्या सरकार रोधी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने एवं किये गए स्थानीय दैनिक मजदूर को नियोजित कराने के साथ मुटा प्रजनन केन्द्र का जीर्णद्वार याताने का विधार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मुटा प्रजनन केन्द्र Captive breeding के लिए उपर्युक्त नहीं होने के कारण इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता।

झारखण्ड सरकार

चन, पर्यावरण एवं जलवायु प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक—5/वियोसो अल्पसूचित प्रश्न—130/2021—**2567** व्यप्ति, दिनांक—**06-09-2021**

प्रतिलिपि—उप सचिव, झारखण्ड विवानसभा, रोधी को उनकी ज्ञाप सं0—2001, दिनांक—02.09.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, भविमहल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रोधी/माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रोधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अधर सचिव

श्रीमती सीता सोरेन, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सदन में पूछा
जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० ००००-०१ से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मंत्री, स्वास्थ्य, विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> क्या यह बात सही है कि चाईबासा के उत्तिष्ठानी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास भी किया जा चुका है. क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार झारखण्ड राज्य भवन निर्माण (निर्माण) के अधीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है परन्तु इस कार्य की जिम्मेदारी कोलकाता की सिपलेक्स इन्फारस्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपी गयी है जिसका निर्माण कार्य बन्द है. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 30 माह में पूरा होनेवाले इस निर्माण कार्य को जल्द पूरा कर मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहती है, हर्ता कब तक नहीं तो क्यों ? 	<p>स्वीकारात्मक।</p> <p>आशिक स्वीकारात्मक। लौकड़ाउन के समय निर्माण कार्य बंद था। अब कार्य प्रगति पर है।</p> <p>निर्माण कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।</p>

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

झापांक-१/विधायी/०६-१६/२०२१ - ५०६(३) स्वा०, री०, दिनांक: ३।९।२१
प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, री० को उनके झाप सं० प्र०- १७८५/वि०त०,
दिनांक-२८.०८.२०२१ के क्रम में २०० (दो सौ) अतिरिक्त प्रतिवेदी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।

(29)

डॉ० लम्बोदर महतो, स०विंस० द्वारा दिनांक-०७.०९.२०२१ को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न स०-अ०स०-१४

वया मंत्री खान एवं भूत्त्व विभाग यह बतलाने की कृपा करें कि-

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
1	वया यह बात सही है कि पूरे राज्य में डीएमएफटी योजना के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अव्यहृत पड़ी है, जिसके विरुद्ध विकास योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पा रही है,	उत्तर आशिक रूप से स्थीकारात्मक है। झारखण्ड में अबतक DMFT कोष में लगभग 7.288 करोड़ रुपये की संग्रहित राशि में से 4.994 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत करने की सूचना है (अनुलग्नक-।)। DMFT Rules, 2016 एवं PMKKKY माइडलाइन के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रबंधकीय समिति की बैठक की अनुशंसा के पश्चात जिलास्तरीय शासी परिषद से अनुमोदन का प्रावधान है।
2	वया यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत कई जिलों में कोविड-१९ महामारी में बचाव के लिए नियमानुकूल टैंडर न करके कोटेश्वन के आधार पर 100 करोड़ से अधिक राशि की वित्तीय अनियमितता बरती रही तथा कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र से बाहर राशि व्यय की रही है;	उत्तर अस्थीकारात्मक है। कोविड-१९ महामारी के बचाव के लिए निम्नलिखित निदेश प्राप्त हैं- 1. खान मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-७ / २ / २०२० -MIV दिनांक-२८.०३.२०२० (अनुलग्नक-II) 2. गृह बारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-१५६० दिनांक-०९.०६.२०२० (अनुलग्नक-III) 3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की नीति कल्याण रोजगार अभियान (पत्रांक-३७१८६४, दिनांक-२२.०६.२०२०) (अनुलग्नक-IV)
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्थीकारात्मक है, तो वया सरकार उपर्युक्त विन्दुओं की जांच कराकर समुचित कार्रवाई करना चाहती है हीं, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त काडिका में स्थिति रपट कर दी रही है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूत्त्व विभाग

ज्ञापांक:-विंस०(अ०स०)-११ / २०२१ १७३८ / ए०, रौची, दिनांक:- ५६-०९-२०२१

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रौची को उनके ज्ञाप स० प्र०-१९०६ दिनांक-३०.०८.२०२१ के सदर्भ में २०० प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

66/१८
सरकार के उप सचिव

सुशील कुमार, I.A.S.
सचिव
Sushil Kumar, I.A.S.
Secretary



(53)
Government of India / भारत सरकार
Ministry of Mines / भूजि विभाग
Tel. : 2338 2814 / 2338 6173
Fax : 2338 6032
E-mail : mcy-mines@gov.in
Website : www.mines.gov.in

DO No. 7/2/2020-MTV
Dated 22nd March 2020

Sub: One-time relaxation in utilization of District Mineral Foundation (DMF) funds for purchase/installation of testing, screening and other equipment/s in connection with COVID-19

To all DMS bdy

Dear Madam/Sir,

As you are well aware, the Central Government has taken various measures to combat the threat posed by the COVID-19 pandemic. The Hon'ble Prime Minister has announced a nationwide lock down for 21 days and also earmarked Rs 15000 crore for healthcare amongst other measures. Further, the Hon'ble PM has announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana with Rs 1.7 Lakh crore outlay on 26.03.2020. One of the components of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana is the utilization of the funds collected under the District Mineral Foundation for medical interventions required for testing and treating the patients affected by COVID-19 pandemic with the aim to supplement the efforts of district administration to curtail the spread of this deadly virus.

2. The Central Government in exercise of the powers conferred under Section 20 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 directed the concerned State Governments to incorporate the Pradhan Mantri Kshem Kalyan Yojana (PMKKY) guidelines into the rules framed by respective State Governments for District Mineral Foundation. The guidelines for implementation of the PMKKY were circulated vide this Ministry order dated 16th September 2015.

3. Now, in exercise of the powers conferred under Section 20 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 read with emergent national interest to combat the COVID-19 pandemic, the following additional instructions are hereby issued for implementation of the projects under PMKKY by utilizing the funds collected under District Mineral Foundation (DMF). These instructions will supplement the already issued guidelines dated 16th December, 2015 by Ministry on this matter.

4. The State Government may utilize the funds available under DMF for supplementing and augmenting facilities of medical testing, screening and other requirements in connection with preventing the spread of COVID-19 pandemic as well as for treating the patients affected with COVID-19 pandemic subject to various instructions issued in this regard by Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India.

भवन नं. 326, 'A' विंग, शहीद शाह, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110 001
Room No. 326, 'A' Wing, Shaheed Bhagat Singh, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001

5. Utilisation of DMP fund as per the above relaxation is subject to the following conditions:

- a. It is to be ensured that the expenditure related to COVID- 19 does not exceed thirty (30) percent of the balance funds available with DMP.
- b. Funds can be utilized for purchase/installation of necessary medical equipment/s or creation of medical infrastructure as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in those districts with at least a minimum of one COVID-19 positive patient.
- c. In all the districts, funds can be used for purchase of face masks, soaps, sanitizers, and food distribution for poor people if other available funds are not sufficient as certified by the district magistrate.
- d. Technical configuration and specification of the equipment/s for COVID- 19 being purchased/installation shall be as per the laid down policies and guidelines of M/o Health and Family Welfare for COVID- 19 and other relevant instructions.
- e. Due processes and procedure shall be followed by district administration while undertaking the purchase/installation of the equipment/s.
- f. It shall be the responsibility of the District Authority to conduct the mandatory audit into the purchase/installation of the protective equipment in connection with COVID-19 under DMP as and when it deems appropriate and feasible.
- g. Extant rules, regulations and codal provisions applicable for DMP are to be followed for any expenditure done to prevent the spread of COVID-19 pandemic.

6. You are requested to direct the concerned authorities to take immediate measures for implementation of the above guidelines.

With regards,

Yours Sincerely,


(Sanjiv Kumar)

Chief Secretary, All State Governments

ग्रामसंघ सरकार
खान एवं पूतल विभाग
खान निदेशालय

मामा-
प्रतीक्षित - जबी उपायुक्त, ग्रामसंघ/सभी विला/सहायक खान एवं व्याविकारी को तृष्णनार्थ एवं
अपना असंबोध देंगे दिलाते।


Sanjiv Kumar
25/12/2020

पत्र संख्या-05 / राजस्थानीमिंट (JSLPS-Covid-19)-18/2020- 15/60 (र)

आरण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन विभाग)

पा. ४८४
राजस्थान विभाग, आपदा
प्रबंधन विभाग
पुस्तकालय, अमृतपुरा
पुस्तकालय में दूसरे
फोन - ०१५३-२६६९२११
ईमेल - miharkhandi@gmail.com

प्रियजन,

सरकार ये सचिव,
राजस्थान विभाग,
आपदा प्रबंधन विभाग,
खान एवं भूत्य विभाग,
आरण्ड, रीवी।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
आरण्ड।

राजी, दिनांक- 09/06/2020

दिवाय:

जूत गाह में नृथ्यमी दीटी कियन के संचालन हेतु District Mineral Foundation Fund में उपलब्ध निधि का उपयोग करने के संबंध में।

प्रसंगः-

Secretary, Ministry of Mines, Govt. of India का अर्द्धसरकारी पत्रांक-7/2/2020-
MIV, दिनांक 28.3.2020।

महाराजा,

उपर्युक्त विषयक विदेशानुसार कहना है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से 2020 के इस राज्य के राष्ट्रीय विभाग में यथा, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से 2020 के दीटी कियन का संचालन किया जा रहा है। कठिय कारणों से 31.05.2020 के पश्चात् इस निधि का संचालन हेतु यथा "नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निधि उपलब्ध कराने में असमर्थता घटक" 2020-21 के 13/03/2020 के दस्तावेज़ द्वारा नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियोजित उपलब्ध किया जाना चाहिए। इस घटक का उपलब्ध कराने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अतः उपलब्ध संस्कारण वित्तानपरामर्श नियम लिये गये हैं।

2020 जून महान् भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक-7/2/2020-MIV, 28.3.2020 विषयक संज्ञन जी कठिया-6(c) में अंकित है कि "In all the districts, funds available for purchase of face masks, soaps, sanitizers and food distribution for poor people are not sufficient as certified by the district magistrate."

2020 जून महान् भारत सरकार के पत्रांक-7/2/2020-MIV, 28.3.2020 विषयक दाता नियंत्रण अधिसूचना सं-2435/एम० दिनांक-24.11.2016, अधिसूचना सं-357/एम० दिनांक-03.02.2017, अधिसूचना सं-106/एम० दिनांक-13.01.2017 का नाम से भूत्यमी दीटी कियन के संचालन हेतु District Mineral Foundation Fund का उपयोग किया जाय।

५०

४ उक्त कार्य हेतु DMFT व्यास परिषद्/प्रबन्धकीय समिति द्वारा जिले व दीर्घी विभाग की
संख्या, लालुको की सूची एवं संख्या तथा उक्त कार्य हेतु यथा का निर्धारण किया जाएगा। इस लालुक
प्रतिविद्युत अधिकारीम द्वारा 12.00 बजे अल्पाहा होगा तथा जिले में राजनीति विभाग की संख्या
दिनांक 31.05.2020 को संघर्षित किशन की संख्या से अधिक नहीं होगी।

५ यदि उक्त कार्य हेतु किसी कारणवश किसी जिले P District Mineral Foundation
अन्तर्गत उपर्युक्त राशि उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में 14वीं जिला आयोग द्वारा उपलब्ध करायी
गयी राशि का इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उपर्योग लायुक्त गंधिव, भारत सरकार, पंचायती राज
मंत्रालय के अर्द्धसरकारी पत्रांक-1101179/2016-FD दिनांक 15.04.2020 के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता
है।

अनु०-इथोला।

विश्वासमाजन,

(अबुबलफेर शिवार्य की०),
सरकार के सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग।

(अमिताम कौशल),
सरकार के सचिव,
आपदा प्रबंधन प्रभाग।

(आराधना पटनायक),
सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक- १५६० (अनु०)

रीढ़ी/दिनांक- ०९/०६/२०२०

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रीची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड रीची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पत्रांक- १५६० (अनु०)

रीढ़ी/दिनांक- ०९/०६/२०२०

प्रतिलिपि- उप सचिव, गुरुद्वय सचिव कार्यालय, झारखण्ड रीची को सूचनार्थ प्रेषित।

पत्रांक- १५६० (अनु०)

रीढ़ी/दिनांक- ०९/०६/२०२०

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड रीची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमिताम कौशल),
सरकार के सचिव।

(अमिताम कौशल),
सरकार के सचिव।



गोपनीय सचिव, नर्सरा
प्रधान
VAGENDRA NATH SINHA, IAS
SECRETARY



49 301
मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री
सचिवालय
नर्सरा भवान
६१८ राजपथ, नई दिल्ली - ११०००११

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi - 110001
Tel: 91-11-23382230, 2114466
Fax: 011 23382408
E-mail: secyrdm@rediffmail.com

D.O. No. J-11060/24/2020-RE-III (371854)

June 22, 2020

Sub: Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan-reg.

Dear Chief Secretary,

You are aware that Hon'ble PM launched "Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan" of 125 days, on 20th June, 2020 with a focus on 25 works and a resource envelop of Rs. 50,000 crore, for the returnee migrant workers and similarly affected rural citizens due to COVID-19 pandemic.

2. This Abhiyaan has been formulated for 116 Districts across six States namely, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand and Odisha (list enclosed). This complements your State's own efforts towards mapping of their skills, addressing their immediate needs and jobs.

3. The Abhiyaan is a convergent effort of 12 different Ministries/Departments of Government of India, namely, Rural Development; Panchayati Raj; Road Transport & Highways; Mines; Drinking Water & Sanitation; Environment, Forest and Climate Change; Railways; Petroleum & Natural Gas; New & Renewable Energy; Defence; Telecommunication and Agriculture Research & Education to expedite implementation of 25 public infrastructure works and works relating to augmentation of livelihood opportunities. I have already shared some details through my DO letter of 18th June 2020, while inviting you to the Launch Ceremony.

4. The objectives of the Abhiyaan are:-

- a) Provide livelihood opportunities to returning migrants and similarly affected rural citizens
- b) Saturate villages with public infrastructure and create livelihood assets viz. Roads, Housing, Anganwadi centre, Panchayat Bhawans, Horticulture, water conservation and harvesting works, and Community Sanitary Complexes among others.
- c) The Program will also prepare for expansion and development of livelihoods over a longer term

Contd...../-

5. Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan intends to achieve those goals through pooling of diverse sources of funds for public works and activities in an extraordinarily short period of time. Accordingly, this will require meticulous planning & selection of works, mobilization of men and material, faster administrative decisions, willing community involvement and highest order participation of the local population. Hence, there is a need to forge an effective partnership of Local, State and Central Governments, with day-to-day monitoring, constant dialogue and complete involvement of all levels of Government. For addressing this mammoth public management challenge, I seek your cooperation, leadership and guidance.

6. Achieving the above in a short period of time would require a very effective and systematic monitoring of progress made in these Districts. Accordingly, we have developed a portal for the same which has Dashboard for District & States as well. Government of India will depute Central Nodal Officers to monitor the progress of the Schemes of all 25 works in close coordination with the States and facilitating dialogue at all levels for resolving issues of implementation.

7. Simultaneously, the State Government would need to put in place an effective monitoring arrangement of the selected Districts. To coordinate this effort at the State level, the State Government may like to nominate ACS/Pr. Secretary Rural Development as the 'Nodal Officer' for the State and may also deploy senior officers to ensure the success of this Abhiyaan. You may like to constitute a mechanism for coordination among the State counterpart Departments.

8. The Deputy Commissioners/District Magistrates/Collectors of these districts will definitely play a very important role along with Zila Parishad Chairman, District Panchayat Heads, Block Pramukhs, Panchayat Samitis, Sarpanch/Pramukh/Pradhan of Gram Panchayat and PRI leadership and other district/block level officers. Effective communication and coordination arrangements would need to be developed connecting various levels too.

9. The willing collaboration of community institutions such as PRIs, SHG networks as well as the elected representatives is extremely important for engaging with citizens. Therefore their involvement, sharing of progress with them and overall architecture and philosophy of the Abhiyaan would need to be explained and emphasized.

10. Media plays an important role, not only in disseminating the message of the campaign to the targeted people, but also provides useful feedback. Accordingly, I request you to consider engaging with all forms of Media including Social Media and sharing information about the campaign.

Contd.....J-

(67)

- 3 -

11. I request you to kindly convene a meeting of all concerned at your level at the earliest to make this Abhiyaan a success. You may need to issue directives at your level on all the relevant aspects for making this Campaign a success.

12. As Nodal Department for Garib Kalyan Rojgar Yojna, I assure you full cooperation from all Government of India Ministries / Departments participating in this Abhiyaan. Sh. Rohit Kumar, Joint Secretary (RE) of my Ministry (e-mail id: gkry.mosd@msd.gov.in) has been nominated as the "Central Coordinator" for this Abhiyaan to coordinate with all the Union Ministries/Departments and the State Governments.

I request you to provide the leadership to the Abhiyaan in your State for its success and fulfill PM's promise to migrant citizens.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Nagendra Nath Sinha)

Chief Secretaries of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha

Copy to: Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of Rural Development, Panchayati Raj Departments and Resident Commissioners of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha.

Copy also to: Secretaries to Government of India of Participating Ministries/Departments

Copy for information to:

1. Principal Secretary to Hon'ble Prime Minister
2. Cabinet Secretary
3. Advisor to Hon'ble Prime Minister

(66)

DMFT Paid in Major and Minor Mineral up to JULY 2021

Sl. No.	Name of District	Coal	Non Coal	Coal + Non Coal	Minor Mineral	(Figure in Rs.)	(Figure in Crs.)
						Total of Major + Minor Minerals	DMF Collection
1	Dhanbad	18367344000	0	18367344000	111033000	18478377000	1847.8
2	Ramgarh	8099345000	0	8099345000	34590000	8133935000	813.4
3	Chatra	8916113000	0	8916113000	77325000	8993438000	899.3
4	Bokaro	6469191000	0	6469191000	81086000	6550277000	655.0
5	Goddar	4508222000	0	4508222000	24271935	4532493935	453.2
6	Hazaribagh	3292843465	0	3292843465	32461403	3325304868	332.5
7	Deoghar	984095000	0	984095000	77762000	1061857000	106.2
8	Ranchi	908110000	0	908110000	106331000	1014441000	101.4
9	Latehar	802158602	14372431	816531033	39544859	836075892	83.6
10	Giridih	155267000	0	155267000	149816000	305083000	30.5
11	Palamu	59086000	676150	59762150	443291000	503059150	50.3
12	Pakur	519814963	0	519814963	760686402	1280501365	128.1
13	Chailasa	0	14966943000	14966943000	87356799	15054299799	1505.4
14	Gumla	0	404115000	404115000	130957000	535072000	53.5
15	Jamshedpur	0	564005000	564005000	207497000	771502000	77.2
16	Lohardaga	0	224053725	224053725	10008751	234062476	23.4
17	Saraikella	0	7508000	7508000	118880000	126388000	12.6
18	Koderma	0	0	0	45184771	45184771	4.5
19	Garhwa	0	0	0	26950528	26950528	2.7
20	Khunti	0	0	0	55509223	55509223	5.6
21	Simdega	0	0	0	62990000	62990000	6.3
22	Jamtara	0	0	0	40514000	40514000	4.1
23	Dumka	0	0	0	195957000	195957000	19.6
24	Sahibganj	0	0	0	724482871	724482871	72.4
Total		53081590030	16181673306	69263263336	3624486542	72887749878	7288.8
Total (in Crs.)		5308.2	1618.2	6926.3	362.4	7288.8	

YEAR OF CONSOLIDATION IN DRAFT (AUDIT NOT YET COMPLETED) (in Million Rupees)

S. No.	District	Name of Assistant Sub-Division	Financial Year 2015-16									
			Revenue	Capital								
1	Bilaspur	Sonari	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Bilaspur	Shantipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Bilaspur	Sarai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Total (in Rs.)	3,599	4,331	30,31	46,49	89,31	88,89	91,96	113,14	33,76	365,45
		Total (in Rs.)	3,599	4,331	30,31	46,49	89,31	88,89	91,96	113,14	33,76	365,45

(S)

(56)

Details of Scheme

Details of Schemes / Projects under implementation	Number of schemes/ projects/Unit	No. of individual beneficiaries assisted (ODF, Trainees, Others)	Amount Allocated (Rs. in Cr.)	Amount spent on date (Rs. in Cr.)
• Drinking water	16742	3148084	3801	2416.70
• Sanitation (ODF) (Swatch Bharat Mission)	18	794551	460.98	377.11
• Health Sector	117	207544	67.43	54.50
• Others	2672	56073	665.29	271.87
TOTAL	19549	4206252	4994.41	3120.18

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०विंस० द्वारा पूछा गया अल्प-सूचित प्रश्न
संख्या-३०स०-१३ का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	वया यह बात रही है कि राज्य में 2021 से अब तक कोविड से 5131 लोगों की मृत्यु सरकारी आकड़ों के अनुसार हुई है।	कोरोना महामारी के Wave-1 एवं Wave-2 दोनों काल में राज्य अंतर्गत सभी जिलों से प्रतिवेदित अभी तक कुल 5132 व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है।
2.	वया यह बात रही है कि मृत व्यक्तियों में सरकारी आकड़ों के अनुसार एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, दर्शाया गया है।	अस्थीकारात्मक। वस्तुतः ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिवेदित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्पीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि कितने भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है तथा सरकार सभी सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लान्ट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्थीकारात्मक। राष्ट्रस्वयं विभाग राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लान्ट लगाने का कार्य किया जा रहा है। PM Care Fund से कुल 38 स्वास्थ्य संरक्षणों जबकि CSR/ State Resource से कुल 34 स्वास्थ्य संरक्षणों में ऑक्सीजन प्लान्ट Installation का कार्य किया जा रहा है जिसे 15 Sept 2021 तक सभी संरक्षणों को पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। गैर सरकारी संरक्षण में कुल 16 संरक्षणों में ऑक्सीजन प्लान्ट Installation का कार्य संपन्न हो चुका है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य विकास, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

झाप सं० : ०८ / विंस०(प्रश्न) -०१ / २०२१-११(०४) रौची, दिनांक - ०४.०९.२०२१

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रौची को उनके झापांक-1907 विंस०, दिनांक

30.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०४.०९.२०२१.
सरकार के संयुक्त सचिव

(3)

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक-07.09.21 को
पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या- ५०८०-२४ का उत्तर प्रतिवेदन।

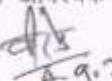
क्र०	प्रश्न	उत्तर
१-	क्या यह बात रही है, कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या-४२१ (९) दिनांक-२२.११.२०१८ द्वारा झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली २०१८ के प्राकार्पानों का अधिसूचना संख्या-८३ (९) दिनांक-२०.०४.२०२० द्वारा किया गया है;	स्वीकारात्मक।
२-	क्या यह बात रही है कि उक्त नियमावली के पूर्व पदस्थापित चिकित्सकों का Wage Protection एवं अन्य लाभ (वर्ष २०१८-२०१८ के बीच पदस्थापित) सरकार के समान विनग तीन (३) बार से प्रक्रियाधीन हैं;	आशिक स्वीकारात्मक।
३-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में उक्त पदस्थापित चिकित्सकों की अन्य सभी लाभ देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना सं०-४२१ (९) दिनांक-२२.११.१८ द्वारा झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, २०१८ अधिसूचित है। तत्पश्चात अधिसं०-८३ (९) दिनांक-२०.०४.२०२० द्वारा उक्त नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन नियमावली की कड़िका-३ के अनुसार झारखण्ड चिकित्सा सेवा संवर्ग के दैसे सरकारी चिकित्सक जिनकी नियुक्ति ट्र्यूटर एवं बीच रेजिडेंट के पद पर नियमावली बनने के पश्चात हुई है, को जो वेतन एवं मता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं मता ट्र्यूटर एवं बीच रेजिडेंट के पद पर नियुक्त अधिकी के लिए देव होगा। सामान्य कटीतियाँ भी नियमानुसार की जायेगी। वर्ष २०१८-१९ के बीच टेन्योर अधिकी पर पदस्थापित झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के नियमित चिकित्सकों को वेतनमान एवं अन्य कटीतियाँ नियमानुसार प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : ९/चिक्की-०६-१९/२०२१ - ५१४(९) रौची, दिनांक-०५.०९.२०२१

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रौची को उनके ज्ञाप संख्या

प्र०- २००० दिनांक- ०२.०९.२०२१ के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 ५.९.२१
 सरकार के अवर सचिव

(३२)

श्री बिरंची नारायण, स०विंस० द्वारा दिनांक—०७.०९.२०२१ को पूछा जाने वाला अल्प सूचित
प्रश्न संख्या—३०स०—२१

व्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
१	व्या यह बत सही है कि बोकारो सहित राज्यमर में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 लागू है, जिसके अन्तर्गत सभी बालू धाटों को ०२ केटेगरी क्रमशः केटेगरी-०१ (जिसके अन्तर्गत २३५ धाट हैं, जिसका संधालन पंचायत के माध्यम से निशुल्क निजी उपयोग हेतु होना है) और केटेगरी-०२ (जिसके अन्तर्गत ३५८ धाट हैं, जिसे JIMMS/JSMDC के माध्यम से कमर्शियल बेचने का प्रावधान है) में विभाजित किया गया है एवं उक्त सभी धाटों में CCTV लगाने तथा बालू के अदैखनन और परिवहन को रोकने हेतु सभी बाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम GPS सिस्टम लगाने का उपयोग किया गया है और इसका भड़ारण, विक्रय एवं प्रेषण हेतु JIMMS/JSMDC पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का निस्तारण जिला खनन कार्यालयों के स्तर से होना है, लेकिन आम नागरिकों को ऐसी कोई भी ऑनलाइन विक्रय की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके तहत उनके स्थल/घरों तक बालू की आपूर्ति हो सकें।	उत्तर आशिक स्पष्ट से स्वीकारात्मक है। Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 एवं District Survey Report (DSR) के अनुसार केटेगरी-१ के बालूधाट पंचायत द्वारा संचालित कराने हेतु जिलास्तर पर कार्रवाई की जाती है। झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिंग, रोधी को केटेगरी-२ के बालूधाट का संचालन का Mandate है। सूचित किया गया है कि १६ बालूधाट संधारित हैं। शेष बालूधाटों के Mining Plan/E.C./CTE/CTO प्रक्रियाएँ हैं तथा MDO का ध्यन हेतु कार्रवाई की जा रही है। ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत JIMMS तथा Vehicle Tracking System के System Integrator का JAP-IT/Data Centre में API Integration हेतु Security/Resecurity प्रक्रिया में है।
२	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो व्या सरकार बालू के अवैध खनन, भड़ारण और प्रेषण पर लगाने हेतु Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 को कठोरता से लागू करवाते हुए सभी बालू धाटों के जिलावार नाम पता / लोकेशन को प्रचारित करते हुए नागरिकों को ऑनलाइन विक्रय की सुविधा देने का विचार स्थिती है हो, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिंग, रोधी द्वारा बालू धाट का विवरण JIMMS Portal पर उपलब्ध है। जैसे-जैसे बालूधाट आवश्यक अनापत्ति के पश्चात सक्रिय होते हैं, वे भी ऑनलाइन कार्य करेंगे।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापाक—विंस०(अ०स०)-१२२५ / एम०, रोधी, दिनांक—०६.०९.२१
प्रतिलिपि—अवर संधिव, झारखण्ड विधान सभा संचिवालय, रोधी को उनके ज्ञाप सं०
प्र०-१९७७ दिनांक—३१.०८.२०२१ के संदर्भ में २०० प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

16/09/21
सरकार के उप संधिव

(93)

1663
06/09/2021

दौ० सरकारी अहमद, मा०सा०वि०सा० से प्राप्त अल्प सुधित प्रश्न संख्या-अ०स०-०६
क्षा माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

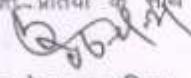
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्षा यह बात सही है कि साज्य के मदरसा में विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन हेतु SPQEM/SPEMM के तहत पूर्णकालिक स्नातक शिक्षक को प्रतिमाह 6000/- रुपये एकमुश्त मानदेय देने का प्रावधान है,	उत्तर आंतरिक लघ से स्वीकारात्मक है। वस्तुप्रियति यह है कि वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय योजना SPQEM (Scheme for Providing Quality Education in Madarsa) और IDMI (Infrastructure Development in Minority Institution) को एक कोन्फ्रंड प्रायोजित योजना के रूप में संबद्ध करते हुए SPEMM (Scheme for Providing Education in Madarsa/Minority) नामकरण किया गया है। वर्तमान में केंद्रांश एवं साज्यांश का अनुपात 60:40 है। ये स्वीकृत बल के विकास कार्यात्मक स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। कोन्फ्रंड प्रायोजित योजना के तहत मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु गणित भाषा एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों दो प्रश्नावान योजना के तहत वार्षिक लघ से रखे जाने का प्रावधान है। कोन्फ्रंड सरकार द्वारा वार्षिक परियोजना अनुमोदन परिषद (PAB) की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा तदनुसार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।
2	क्षा यह बात सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत साज्य के 88 मदरसों में 179 कार्यरत शिक्षकों को विगत 6 वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षक आर्थिक तंगी एवं नुखमरी के कागार पर हैं,	उत्तर आंतरिक लघ से स्वीकारात्मक है। वस्तुप्रियति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक परियोजना अनुमोदन परिषद (PAB) की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा तदनुसार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। तथा वर्षावार स्वीकृत योजना के अनुसूच्य योजना का कार्यान्वयन (शिक्षकों का मानदेय भुगतान सहित) किया जाता है। विभागीय पत्रांक 1155 दिनांक 28.04.2011 से स्पष्ट है कि इन शिक्षकों का मात्र 01 वर्ष के लिये रखा जाता है तथा योजना की स्वीकृति के उपरान्त इस योजना की राशि को व्यय करने संबंधी निर्णीत पत्र में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षकों को 01 वर्ष के लिये आधुनिक विषयों में मानदेय की आधार पर रखा जाना है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्षा सरकार खण्ड-2 में वर्णित शिक्षकों के बाब्या मानदेय का भुगतान शीघ्र करने का विचार रखती है, हीं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	केन्द्रीय योजना/कोन्फ्रंड प्रायोजित योजना के तहत राशि भारत सरकार से वर्ष 2014-15 तक प्राप्त हुआ तथा प्राप्त राशि को मदरसों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015-16 के बाद इस योजना हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हो पायी है। विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा कि भारत सरकार राशि उपलब्ध करा दे। विभागीय पत्रांक 1201 दिनांक 28.07.2021 द्वारा समस्त कागजातों को उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार को स्वारित किया गया है। राशि प्राप्त होते ही नियमानुसार मानदेय भुगतान किया जा सकेगा।

6.09.21

सरकार के अवृद्ध सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ब्रापांक-10 / वि.स.01-113 / 2021 | 6.63 रोन्ही, दिनांक 06/09/2021
प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखण्ड शिधानसभा सचिवालय, रोन्ही को अतिरिक्त प्रतियों के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

(३५)

श्री संजीव सरदार, माननीय स०विंस० द्वारा पूछा गया अल्पसूचित प्रश्न
संख्या—अ०स०—२६ का उत्तर प्रतिवेदन।

१. क्या यह बात सही कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत प्रखण्ड—दुमरिया, के बाकुलबंदा ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो गया है ;	स्वीकारात्मक।
२. क्या यह बात सही कि निर्मित भवन का हस्तांतरण नहीं होने के कारण आम घामीणों का समुचित चिकित्सीय उपचार नहीं हो पर रहा है ;	स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुमरिया एवं क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में आम घामीण जन को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
३. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्मित भवन को हस्तांतरित करते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित कराने का विचार रखती है, हो तो नहीं क्यों ?	निर्मित भवन के हस्तांतरण के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य विभिन्ना, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : १५ / वि०स०—०७—५२ / २०२१..२४८(१५)

राँची, दिनांक—०५.०९.२०२१

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक—१९९९ वि०स०, दिनांक

०२.०९.२०२१ के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*मेरा
०५.०९.२०२१*
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मधुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सदब में पूछ जाने वाला
अल्प सूचित प्रश्न सं०-आ०स०-१७ का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रिस्स मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, राँची में व्यूरो विभाग में बेड की संख्या काफी कम है ;	आंशिक स्वीकारत्मक। रिस्स, राँची में व्यूरो लर्जरी विभाग में बेड की संख्या 110 है एवं मरीजों की संख्या अधिक है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी जिलों के नरीज अपना इलाज कराने रिस्स में आते हैं तथा व्यूरो विभाग अन्तर्गत बेड की संख्या कम रहने से मरीजों को बेड बही भिलता है और उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है ;	आंशिक स्वीकारत्मक। बेड की कमी के कारण मरीजों के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिभूत रखते हुए यथासंभव स्वानीय व्यवस्था करते हुए इलाज करना चाहता है। रिस्स प्रशासन द्वारा उन्हें यथा सम्भव समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार रिस्स के व्यूरो विभाग ने मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिस्स, राँची में बेड की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिकट भविष्य में बेड की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-11/रिस्स (वि० स०)-05-07/2021स्था०- 361(11) दिनांक:- 04/09/2021

प्रतिलिपि:-अधर संचित, झारखण्ड विधान सभा संघिवालय, को उनके ज्ञाप सं० 1906/वि०स० दिनांक- 30.08.2021 के आलोक में 200 प्रतिवारों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ब्लॉक/२०२,
सरकार के उप संचित।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय सर्वियोसो द्वारा दिनांक-07.09.2021 को पूछे जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं-०-अ०स०-१२ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 84,700 हेक्टेयर वन भूमि सीमांकित क्षेत्र है जिन्हें जमी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।	राज्य के अंतर्गत ऐसी वन भूमि जो सीमांकित है परन्तु अधिसूचित नहीं है, से संबंधित वनों के ढाटा संग्रहण एवं सत्यापन वा कार्य चल रहा है। अभी तक की स्थिति के अनुसार 90,823 हेक्टेयर वन भूमि ऐसी पायी गई है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के 747 गाँव के नवशो के वन बदोबस्ती पदाधिकारी वा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है,	वन बदोबस्ती कार्य पूर्ण होने के बाद वन भूमि के नवशो वन बदोबस्ती पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षित कर सत्यापित किये जाने थे, परन्तु कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं जिनमें नवशो पर उपर्युक्त पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। विभाग का मानना है कि वन बदोबस्ती वा कार्य 1955-67 के द्विच संपन्न किया गया था तथा इस हेतु नियुक्त वन बदोबस्ती पदाधिकारियों द्वारा कार्य अद्यानक बद वर दिये जाने के कारण समवत् ऐसा हुआ।
3. क्या यह बात सही है कि जमावदी नवशो पर वन भूमि का सीमांकन कार्य नहीं होने के कारण वन भूमि का अनाधिकृत खरीद और बिक्री हो रही है।	वन भूमि की अनाधिकृत खरीद और बिक्री रोकने के लिए वन भूमि की विवरणी राजित्य, नियंत्रण एवं भूमि सुधार विभाग की नियंत्रित लिस्ट में शामिल करने हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त को वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो वया सरकार राज्य के 84,700 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित करके 747 गाँवों के नवशो को सत्यापित करवाने वा विवार रखती है, तो कब तक नहीं तो क्यों?	वन भूमि से संबंधित सभी प्रकार के मामलों की समीक्षा हेतु संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक वी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जो इन मामलों की गहन समीक्षा कर रही है। पूरे राज्य की वनभूमि का मामला है और अभिलेख काफी पुराने हैं (लगभग 60-70 वर्ष पूर्व) इस जटिलता को व्याप्ति में रखकर ही सभी जिलों के अपर समहत्ता एवं बदोबस्ती पदाधिकारियों को भी इस समिति में रखा गया है ताकि राजित्य विभाग के अभिलेखों से भी समन्वय हो सके। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झापंक-५ / विं०३० अल्पसूचित प्रश्न-१२६/२०२१- 2568 वा००, दिनांक- ०६.०९.२०२१

प्रतिलिपि-उप सचिव, झारखण्ड विवानसभा, रीवी को उनके ज्ञाप सं-१९०९, दिनांक-३०.०८.२०२१ के प्रसंग ने अतिरिक्त 200 प्रतिवें के साथ/उप सचिव, मार्गिमंडल सचिवालय एवं निवानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रीवी/माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रीवी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
(अमर कुमार सिंह)
सरकार के जायर सचिव

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0विंस0 द्वारा पूछा गया अल्प-सूचित प्रश्न
संख्या-अ0स०-4 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	वया यह बात सही है कि राज्य में कोविड संक्रमण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव में 5131 की घोषित रूप से एवं अधोवित रूप से 20 हजार से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई।	कोरोना महामारी के Wave-1 तथा Wave-2 दोनों काल में राज्यान्तर्गत सभी जिलों से प्रतिवेदित अभी तक कुल 5132 घटितियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है।
2.	वया यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक व सुविधा का घोर अभाव है, साथ ही मृतक के आश्रितों को अवताक कोई मुआवजा की घोषणा नहीं हुई।	राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक नियुक्त हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है एवं पुनः विज्ञापन सं0 01/2021/HRHMS-SMO/MO दिनांक 16.08.2021 द्वारा नियुक्त की प्रक्रिया चल रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो वया सरकार मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दुरुस्त करने का विचार रखती है, हो, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इगरजेसी कोविड रिसॉर्स प्लान (ECRP Phase-II) के अन्तर्गत बजट का प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर PHC Infrastructure को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं विभाग स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। जिलान्तर्गत रिक्त पदों को उच्च प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/विंस0-06-15/2021.59(21)

राँची, दिनांक - 04/09/2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-1786 विंस0, दिनांक

26.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५३८९
०६.९.२०२१
सरकार के उप सचिव।

(38)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का षष्ठम (मानसून) सत्र में दिनांक 07.09.2021 को प्रो। स्टीफन मराण्डी, माननीय सीविंसो द्वारा पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं० अ०स०-२० का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न

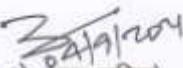
उत्तर

1. क्या यह बात सही है कि निम्नतर पद से उच्चतर पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार देने के पूर्व वरीयता सह योग्यता अथवा लागू सम्बन्धीय नियमादली के क्रम में निर्धारित अहता पदाधिकारियों की सूची बनाते हुए आरक्षण नीति का अकारण अनुपालन करना अनिवार्य है ;
— स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि इस संबंध में कार्निक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-442 दिनांक 25.01.2006 में दिशा निर्देश भी जारी की थी;
— स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण संस्थान में आरक्षण के अनुसार एक भी अनुसूचित जाति के शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है;
— अस्वीकारात्मक
वर्तमान में दो अनुसूचित जाति (श्री सत्यदेव राम-राजकीय महिला पोलिटेक्निक, खोकारी एवं श्री राजेश कुमार, राजकीय पोलिटेक्निक, कोडरमा) के व्याच्याता प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थापित हैं।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निम्नतर पद से उच्चतर पद के प्रभार में की गई प्रतिनियुक्ति की समीक्षा करते हुए अनुसूचित जाति के शिक्षक को आरक्षण के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिलाने का इच्छा रखती है, यदि ही तो कब तक, नहीं तो क्यों ?
— उक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।



उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपालहाउस, डोरण्डा, नीमी

ज्ञापांक— HTESDeec1/VIDHAN SABHA - 4/2021- — 862 / राँची, दिनांक— ०४.०९.२०२१
प्रतिलिपि :—अवर संघिय, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1965 दिनांक 31.08.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(सरकार के अवर संघिय)

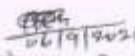
३५

श्रीमती ममता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-07.09.2021 को पूछे जाने वाले
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०स०-२९ का उत्तर -

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	<p>क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला मुख्यालय थाना चौक के नजदीक दामोदर नदी के किनारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा विधि विधान से स्थापित की गयी है, जहाँ आमजनों द्वारा वर्ष से बाहू की ध्यान में एक मूर्जियम एवं पार्क बनाये जाने तथा अद्युत कलाम आजाद के नाम पर एक पुस्तकालय बनाये जाने की मींग छी जारी रही है;</p>	<p>आर्थिक स्थीकारात्मक है। प्रश्नगत क्षेत्र छावनी परिषद, रामगढ़ के क्षेत्राधिकार में आता है। मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, रामगढ़ के पत्रांक-८/VIII/Gen/दिनांक-०६.०९.२०२१ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र में मूर्जियम, पार्क एवं पुस्तकालय बनाये जाने की मांग कभी उनके कार्यालय से नहीं की गयी है।</p>
2	<p>यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्थीकारात्मक है, तो वया सरकार व्यापक लोक हित में खण्ड-०१ में वर्णित स्थल पर मूर्जियम एवं पुस्तकालय का निर्माण कराना चाहती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</p>	<p>नगर विकास एवं आयास विभाग, झारखण्ड द्वारा उक्त प्रश्न में अकित विषयवस्तु के संबंध में उपायुक्त, रामगढ़ से एक प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। उपायुक्त, रामगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।</p>

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आयास विभाग

शापोक-०५/न०वि०/वि०स० अल्प सूचित-०८/२०२१ २७४७ रुची, दिनांक : ०६/०९/२१
प्रतिलिपि-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप संबंध-२००२ वि०स० दिनांक-
०२.०९.२०२१ के आलोक में उत्तर सामग्री की २०० (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 सरकार के अवैर सचिव।

(40)

1645
०५/०९/२०२१

श्रीमती रीता शर्मेन, माइसोविंसो से प्राप्त अल्प सूचित प्रहन संख्या-३०७०-०२
वया मानवीय नक्षी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करें कि-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	वया यह बात सही है कि सरकार कैबिनेट की बैठक में JSSC की प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अधिकारीय के लिए जरूरी कर दिया गया है।	उत्तर आशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना सख्ता 418 दिनांक 10.08.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (राजातक स्तर), सचालन (लालौधन) नियमावली, 2021 ने इस तरह के प्राप्तान किये गये हैं।
2	वया यह बात सही है कि राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारम्भिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक नियमित रूप से नहीं होती है।	<p>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक (+2 विद्यालयों) में राज्य के जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिये निम्न व्यवस्था की गयी है -</p> <p>1. राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा पद पर नियुक्ति के अहेतु के रूप में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में द्वितीय भाषा के रूप में राज्य के 01 जनजातीय भाषा की परीक्षा अनिवार्य की गयी है, ताकि भाषा के जानकार शिक्षक नियुक्त हो सके।</p> <p>2. राज्य में समग्र शिक्षा अभियान (लल्लाल समय में सर्व शिक्षा अभियान) के तहत लगभग 60 हजार पारा शिक्षकों द्वारा पठन-पाठन का कार्य संपादन किया जाता है। ये सभी पारा शिक्षक अपने पद्धायत/प्रखण्ड/गिला में शिक्षण कार्य करते हैं तथा स्थानीय होने के कारण ये उस भाषा के जानकार होते हैं तथा इन शिक्षकों के माध्यम से भी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है।</p> <p>3. प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों का संघर्ष भी जिलास्तरीय होता है और जिला स्तर पर नियुक्ति होने के कारण संबंधित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के जानकार शिक्षक का ही जिलान्तरीत पदस्थापन होता है। इस प्रकार भी प्रारम्भिक विद्यालय के छात्रों को जनजातीय भाषा के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता होती है।</p> <p>माध्यमिक विद्यालयों में जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जा सके। इस हेतु क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसुध नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। माध्यमिक विद्यालय हेतु नियारित भानक में भाषा के 04 पद प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत किये गये हैं। हिन्दी, अरोजी, संस्कृत, उर्दू, कारबी, अरवी, बंगला, उडिया, संथाली, हो, मुडारी, कुखुल एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सभी क्षेत्रीय भाषाओं सहित में से नियमानुसार 04 भाषाओं (जनजातीय भाषा सहित) का चयन विद्यालय की प्रबंध समिति अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कर सकती है। माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक 400</p>

		होकीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षक नियुक्त हो कार्य कर रहे हैं। राज्य में जो भी +2 विद्यालय हैं, वे सभी उच्च विद्यालय से उत्क्रमित किये गये हैं तबा उच्च विद्यालय के शिक्षकों से +2 विद्यालय का पठन-पाठन का कार्य भी लिया जाता है तथा उच्च विद्यालय के शिक्षक (जनजातीय/होकीय भाषा के शिक्षक) सहित +2 विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य करते हैं तथा इसी कारण से +2 विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ का सृजन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक एवं मध्यमिक से +2 विद्यालय स्तर तक के विद्यालयों में जनजातीय/होकीय भाषाओं की पढ़ाई हेतु समृद्धि व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के होकीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारम्भिक कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित रूप से शुरू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-2 में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10 / वि.स.01-115/2021 1645 रोकी, दिनांक 05/09/2021

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा संयिदालय, रोकी को अतिरिक्त प्रतिवेदी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(२४) (५७)

श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-०७.०९.२०२१ को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न
संख्या-अ०स०-०२ से संबन्धित उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
१. क्या यह बात सही है कि सरकार कैडिट की बैठक में ISSC की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हीरीय भाषा का जान होना अध्यार्थियों के लिए ज़रूरी कर दिया गया है ?	स्वीकारात्मक।
२. क्या यह बात सही है कि राज्य के हीरीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक नियमित क्रम से नहीं होती है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। रीधी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में जनजातीय एवं हीरीय भाषा के कुल 165 पद स्वीकृत के विकास 32 शिक्षक एवं घटी आधारित 120 शिक्षक कार्यरत हैं। कौल्हल विश्वविद्यालय में हीरीय भाषा के स्वीकृत पद 08 के विकास 03 शिक्षक कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय में 06 हीरीय भाषाओं के कुल 159 पट्टी के सूजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विनोद भावे विश्वविद्यालय, हुजारीबाग अन्नपूर्ण 06 माह का स्टार्टिफिकेट छोरे की पढ़ाई होती है। इस महाविद्यालय में 07 हीरीय जनजातीय भाषा के 49 शिक्षकों के पट्टी के सूजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लिंगो-बण्डु नुर्मि विश्वविद्यालय, दुमका में हीरीय भाषा के 18 स्वीकृत पद के विकास 06 घटी आधारित शिक्षक कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय में 03 हीरीय एवं जनजातीय भाषा के 35 पट्टी के सूजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। डॉ. रमामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रीधी में हीरीय भाषा के 20 स्वीकृत पद के विकास 05 शिक्षक कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय में पट्टी के सूजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नीलगंगा वीलगंगा विश्वविद्यालय में हीरीय भाषा के 08 स्वीकृत पद के विकास 02 शिक्षक कार्यरत हैं। विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय से पट्टी का सूजन का प्रस्ताव की जायी है। बिनोद बिहारी महोली बैंगलोर विश्वविद्यालय, खनबाद में 6 महीने का खोरता, कुरमाली एवं संधाली विषय की पढ़ाई होती है। इस विश्वविद्यालय में 24 शिक्षकों के पट्टी के सूजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
३. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शज्य के हीरीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित क्रम से शुरू कराना चाहती है यदि हाँ हो काबूलक, नहीं तो क्या ?	उत्तर कंडिका-२ में लिहित है।

इत्यांत सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

१२९

जायंक-०१/वि०स०-०४/२०२१ / राती, दिनांक- ०५/०९/२०२१

प्रतिपिणि- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पञ्चों-१७८८ दिनांक-२६.०८.२०२१ के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दीक्षित।

Shashi
०५/९/२१
(तुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न
संख्या— अ०स०— 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष-2018-19 में रिस्ट्रेक्शन ने पीजी डिप्लोमा में नामांकन भेड़िकल कमीशन द्वारा निर्धारित सीमा से कम अंक प्राप्त छात्रों का नामांकन किया गया है ;	वर्ष 2018-19 में पीजी० डिप्लोमा कोर्स में एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहंताक से कम अंक प्राप्त होने वाले दो छात्रों का नामांकन रिस्ट्रेक्शन नींवी के अन्तर्गत होने के मामला संझान में आया था, जिसमें से एक छात्र का मामला सही पाया गया। उल्लेखनीय है कि पीजी० पाठ्यक्रम में राज्य कोटा के सीटों पर नामांकन हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा राज्यालाकार का जायोजन किया जाता है तथा इसमें पर्षद द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों का नामांकन संबंधित विकास महाविद्यालय में किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्थानीय विभाग के संज्ञान में रहते हुए भी अबतक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गयी है ;	वर्ष 2018-19 में एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहंताक से कम अंक प्राप्त करने वाले नामांकित अभ्यर्थियों के संबंध में निवेशक, रिस्ट्रेक्शन, रींवी तथा परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड रायुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद से संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने हेतु नाम चिन्हित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि उनके विरुद्ध विविसम्भत कार्रवाई की जा सके। निवेशक, रिस्ट्रेक्शन, रींवी से प्रतिवेदन जप्रापत रहने की विधति में स्थानित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 30 दिनों के समय सीमा के अन्दर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हो तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिस्ट्रेक्शन, रींवी में वर्ष 2018-19 में पीजी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहंताक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र के नामांकन के संबंध में दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, विकास शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : ९/विधायी-०६-१७/२०२१ ५१३(७) रींवी, दिनांक-५/९/२१
प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रींवी को उनके ज्ञाप संख्या प्र०— 1908 दिनांक— 30-08-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(४२)

श्री राज सिंहा, स०विंस० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक-07.09.2021 को
पुष्टित अल्प-सुचित प्रश्न संख्या -अ०स०-०३ का उत्तर-

प्रश्नक्रति		उत्तर दाता
श्री राज सिंहा, सादस्य विधान सभा		श्री हरपीजूल हसग, माननीय मंत्री पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड राज्य।
क्र०	प्रश्न	उत्तर
१	वया यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में आवासीय और डे-बोर्डिंग सेंटर संचालित हैं परन्तु उनमें समुचित संख्या में खेल प्रशिक्षण प्रतिनियुक्त नहीं हैं;	अरवीकारात्मक। सभी संचालित आवासीय एवं डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में संविदा/मानदेय पर प्रशिक्षक कार्यरत हैं।
२	वया यह बात सही है कि आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र में कुल 18 खेल प्रशिक्षक ही कार्यरत हैं जिसके कारण खेल प्रशिक्षणों (मन्त्र खिलाड़ियों) के खेल प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों पर असर पड़ रहा है;	अरवीकारात्मक। खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय अंतर्गत कुल 33 आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। इनमें से 18 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षक वीं नियुक्ति संविदा पर वीं गई है, जबकि शेष कोडा प्रशिक्षण केन्द्रों में मानदेय के आधार पर प्रशिक्षक रखे गए हैं।
३	वया यह बात सही है कि आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र और डे-बोर्डिंग सेंटर के खेल प्रशिक्षकों से अनुबंध के आधार पर ही पिछले 10 सालों से सेवा दी जा सी है और उन्हें नियत मानदेय के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाती है;	आर्थिक स्वीकारात्मक। सभी आवासीय एवं डे-बोर्डिंग वीडा प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य के आलोक में प्रतिमाह संविदा राशि/नियत मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलाधी कल्याण कोष अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षकों को चिकित्सीय इलाज एवं नृत्य की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
४	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सदीकारात्मक हैं, तो वया सरकार आवासीय खेल प्रशिक्षण और डे-बोर्डिंग सेंटरों के खेल प्रशिक्षकों की सेवा नियमित करने एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का विचार रखती है, हूँ तो क्या उक, नहीं तो क्यों ?	आवासीय एवं डे-बोर्डिंग के प्रशिक्षकों की मूल नियुक्ति संविदा एवं मानदेय के आधार पर ही वीं गई है। तथा एवं मानदेय आवासीय कर्मियों की सेवा नियमरिकरण नीतिगत बाध्यता है जिस पर सकाम प्राधिकार द्वारा निर्धारित निदेश एवं नियम के आलोक में ही समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

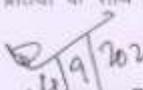
झारखण्ड सरकार

पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

आपाका : पर्य०/विंस०-९७/२०२१-२४२

रोची, दिनांक ०५.०९.२०२१

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड किधान सभा संविदालय, झारखण्ड, रोची को उनके ज्ञाप सं-
1783/विंस०, दिनांक-26.08.2021 के प्रस्ताव में 200 प्रतियों के साथ सुचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संपूर्ण संविधान
परिवर्तन, जल संरक्षण, विनियोग एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, रोची।

(43)

प्रश्न

(43)

उत्तर

5. क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के 16% (सोलह) व्याख्याता कार्यरत है,
- आशिक स्वीकारात्मक वस्तुत दर्तनाम में राज्य के सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के 15% (पद्धत) व्याख्याता कार्यरत है।
6. क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2535 दिनांक 16.10.2015 के कड़िका संख्या 12 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्याख्याताओं को प्रोन्नति में आरक्षण देय है;
- आशिक स्वीकारात्मक विभागीय अधिसूचना सं 2535 दिनांक 16.10.2015 के कड़िका 12 में प्राप्तवानित है कि— “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के उपबंध के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्यर्थी के बाहे में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। संवर्गीय एकल पद में आरक्षण व्यवरथा लागू नहीं होगी।” व्याख्याता का पद योग्य राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में शृंजित है। इसके अतिरिक्त राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में विभागाभ्यक्ष एवं प्राचार्य का पद है। उक्त सभी पदों पर झारखण्ड लोक रोपा आयोग की अनुशंसा पर सीधी नियुक्ति होती है। व्याख्याता से विभागाभ्यक्ष/प्राचार्य में प्रोन्नति का प्रावधान नहीं होता है। उक्त पद पर कार्यरत व्याख्याताओं को मात्र वित्तीय उन्नयन का लाभ तकनीकी शिक्षा रोपा नियामावली के खण्ड IV (कड़िका 11) में AICTE द्वारा अनुशासित CAS के तहत दिया जाता है। AICTE द्वारा अनुशासित Career Advancement Scheme (CAS) के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। वरन् जो भी व्याख्याता नियारित योग्यता एवं अनुभव/प्रशिक्षण घारित करते हैं, उन सभी को लाभ दिया जाता है। उक्त प्रोन्नति के उपरान्त व्याख्याता के मूल धारित पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
7. क्या यह बात सही है कि संकल्प संख्या-918 दिनांक 01.02.2021 द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 26% प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया है;
- स्वीकारात्मक
8. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के व्याख्याताओं की 26% आरक्षण के तहत प्रोन्नति देने का विधार रखती है, यदि ही तो कद तक, नहीं तो क्यों ?
- कड़िका 2 के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।



उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपालहाउस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक—HTESDsec1/VIDHAN SABHA -5/2021— 863 /रौधी, दिनांक—04.09.2021
प्रातिलिपि—अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा संविधालय को उनके ज्ञापांक 1964 दिनांक 31.08.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित।

3/2021/002
(सरकार के उत्तर सचिव)

(44)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सर्विंसो द्वारा दिनांक—07.09.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या—अ०स०—०७ की उत्तर सामग्री:-

प्रश्न	उत्तर
1— पूछा यह बात सही है कि गिरिढीह रम्पू प्रदूषण के पूर्णवत् क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिश्वानों द्वारा बड़े पैमाने पर जहरीली गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है।	अस्थीकारात्मक। गिरिढीह सदर प्रखण्ड के पूर्णवत् क्षेत्र में कुछ कारबने हैं यथा स्वीज आयरन, पीण आयरन, इफडवर्शन पर्स, लैटिंग गैल एवं राईस गैल स्थापित हैं। विभिन्न गैसों का उत्सर्जन स्थानाधिक है।
2— क्या यह बात सही है कि जहरीली गैस के कारण इस क्षेत्र में इधर रोग से संबंधित एवं अन्य तरह की बीमारी हो रही है, जिसके कारण बच्चे अपेक्षित अस्वस्था पैदा ले रहे हैं एवं जल, वायु एवं मृदा प्रदूषित होने के कारण बच्चों के जननानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।	उसीलों से बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या की परिशिष्ट सूचना इस कार्यालय को नहीं है। स्वास्थ्य, पिकिंसा रिहा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गिरिढीह जिला अंतर्गत औद्योगिक प्रतिश्वानों के द्वारा बड़े पैमाने पर जहरीली गैस के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ—
3— यदि उक्त स्थानों के उत्तर स्तरिकारात्मक है, तो क्या सरकार जहरीली गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु सघन पूष्टारोपण एवं पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु अन्य दोस कदम उठाकर जननानस को राहत दिलना चाहती है, हो, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. वायु प्रदूषण—इसके तहत Upper Respiratory Tract infection, Asthma silicosis etc बीमारियों की संख्या बढ़ी है, जिसका समय समय पर कैम्प लगाकर ऊपरिनियोग कराया जाता है एवं समुचित इलाज दिया जाता है। 2. जल एवं वायु प्रदूषण के कारण संभवतः इस क्षेत्र के बच्चों में अवंगता एवं अस्वस्थता की स्थिति पायी जा रही है। जिसकी पुष्टि हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रिजनल ऑफिसर प्रदूषण विभाग के साथ समवय स्थापित करते हुए मृदा एवं जल की जीव हेतु अद्यतार कार्रवाई की जा रही है। विभागीय पत्रांक—2517 दिनांक—01.09.2021 पत्रांक—2550 दिनांक—03.09.2021 द्वारा कृपि. पशुपालन एवं साहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) /निदेशक, उच्चोग, ब्राह्मणपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

ज्ञारखण्ड सरकार

बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झापांक-05/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न-116/2021-**2575**व०प०, राँची, दिनांक-**06-09-2021**

प्रतिलिपि—उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-1791 दिनांक-26.08.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतिवार्षी के सवार/उप सचिव, भविमंडल संधिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री को आपा सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संतोष कुमार थोरा
6-9-21

(संतोष कुमार थोरा)
सरकार के अवर सचिव

(15)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का बष्टम (मानसून) सत्र में दिनांक 07.09.2021 को श्री डुलू महतो
माननीय संविधान सभा पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं 0 असू-22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न

1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में
एक मात्र अभियंत्रण कॉलेज बी0आईटी०
सिन्दरी है, जो राज्य गठन के उपरान्त
झारखण्ड को मिला और बिहार को 3 सरकारी
अभियंत्रण कॉलेज मिला और 20 वर्षों के बाद
झारखण्ड में एक मात्र बी0आईटी० सिन्दरी
ही रहा जबकि बिहार राज्य में 20 वर्षों के
बाद 3 के जगह 38 सरकारी अभियंत्रण
कॉलेज मौजूद हैं।
2. क्या यह बात सही है कि बी0आईटी०
सिन्दरी में राज्य के गरीब गुरुज्ञा के बच्चों उच्चा
तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस
संस्थान की अपनी एक गरिमा है परन्तु
संस्थान के निदेशक की नियुक्ति 2020 के
बाद अभी तक नहीं की गई है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,
तो क्या सरकार बी0आईटी० सिन्दरी में नये
निदेशक की नियुक्ति एवं अपने अधीन ही पूर्ण
की संस्थान को संपोषित करना चाहती है,
यदि ही हो तो कब तक, नहीं हो क्यों?

उत्तर

- स्वीकारात्मक।
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा
के आलोक में बी0आईटी० सिन्दरी में
निदेशक के पद पर श्री धर्मेन्द्र कुमार
सिंह, की नियमित नियुक्ति विभागीय
अधिसूचना सं0-39 दिनांक 09.01.2017
द्वारा की जा चुकी है।
- उक्त के आलोक में प्रश्न नहीं
उठता है।



उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपालहाटा, दौर्घटा, गैंडी

ज्ञापांक- HTESDsec1/VIDHAN SABHA-3/2021- — 864 /रोधी, दिनांक- 04.09.2021
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1966 दिनांक 31.08.2021 के
आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सरकार के अवर सचिव)

(५७)

श्री दशरथ गागरहैं, माननीय स०विंस० द्वारा दिनांक-07.09.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न
संख्या-आ०स०-28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड में Human Resource Policy नहीं है;	स्थीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड में Human Resource Policy नहीं के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हुई नियुक्तियों में 90% राज्य के बाहरी लोगों की नियुक्ति हुई है;	अस्थीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत की जाने वाली नियुक्तियों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजनीति विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत नियुक्तियों का पालन किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2022 तक भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वेतनमान एवं घेठ पे के आधार पर किया जाना है;	अस्थीकारात्मक। इस संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा-निदेश प्राप्त नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्थीकारात्मक है, तो क्या सरकार बर्तमान वित्तीय वर्ष में ही Human Resource Policy और कार्मियों को वेतनमान एवं घेठ-पे लागू करने का विचार-रखाती है, हों तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा Human Resource Policy का प्रारूप तैयार कर तकनीकी मंत्रिया हेतु भारत सरकार की अनुषंगिक इकाई NHSRC, नई दिल्ली को भेजा गया है। उक्त के क्रम में HR Division, नई दिल्ली से नियोग प्राप्त हुआ कि उनके द्वारा एक Uniform HR Policy बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही राज्यों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसे राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार सुधार करते हुए लागू कर सकता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

झापांक-21 / विधान सभा-06-16/2021- 64 (21) रक्त/रीची, दिनांक 06-9-2021
प्रतिलिपि:-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रीची को उनके श्वाप संख्या-1997/विंस० दिनांक-02.09.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य सरकार के उप सचिव।

ठों० लम्बोदर महातो, गा०स०पि०ख० से प्राप्त अल्प सुवित प्रश्न संख्या-ज०ख०-२३
उपा मन्त्रीय मत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतालगे की कृपा करेगे कि-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित जिक्रके बयन हेतु परीक्षा ली गई थी और वर्ष-2019 में परिणाम के पश्चात चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक- 5974 दिनांक 23.11.2020 के तहत डाकखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या- 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों से नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था।	उत्तर आर्थिक रूप से स्वीकारात्मक है। बस्तुत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 5974 दिनांक 23.11.2020 द्वारा डाकखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया था।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विज्ञापन संख्या- 21/2016 के आधार पर गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास एवं अन्य लिखित प्रश्नों के सफल अन्वर्तीयों को नियुक्ति पत्र देने का विचार रखती है, हीं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, डाकखण्ड के पत्रांक 1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा डाकखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर तत्काल रोक हटने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार के अवर सचिव।

डाकखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रापांक-10 / वि.स.01-121/2021 1639

राँची, दिनांक ०५/०९/२०२१

प्रतिलिपि:- उप सचिव, डाकखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक १८८४ / रोड़ी

दिनांक ६/९/२०२१

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-1903, दिनांक 30.08.2021 के प्रसंग में वाचित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मुख्यमंत्री)
सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि का वाचित विवर	
नाम	मुख्यमंत्री
पद	मुख्यमंत्री
विषय	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रतिलिपि का वाचित विवर	मुख्यमंत्री का वाचित विवर नहीं दिया गया।

प्रतिलिपि का वाचित विवर	
नाम	मुख्यमंत्री
पद	मुख्यमंत्री
विषय	सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ